(ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना के अंतर्गत आंशिक मुआवजा और पुनर्वास हेतु 82280 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कब तक रादू परियोजना को स्वीकृति देने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) केन्द्रीय जल आयोग में राडू सिंचाई परियोजना का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राडू जलाशय परियोजना का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में 9/89 में प्राप्त हुआ था। जांच के बाद परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को 1990 में वापस भेज दी गई थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय है। सिंचाई परियोजनाओं को आयोजना, अनुदान एवं कार्यान्वयन राज्य सरकारें अपने स्वयं संसाधनों से करती हैं। तथापि, परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार की प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

Allocation to Punjab from Central Road Fund

3029. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the amount allocated to the State of Punjab from the Central Road Fund during the years 1993-94, 1994-95 and 1995-96;

(b) whether any amount is proposed to be sanctioned for the State for the year 1996-97;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) The amount allocated to Punjab, from the Central Road Fund during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 is given below:—

(Rs. in lakhs)

Year	Amount
1993-94	60.00
1994-95	259.00
1995-96	213.00

(b) to (d) The amount for the year 1996-97 will be released, after the Demands for Grants are passed by the Parliament.

Violation of the Jute Packaging Material Act by Fertilizer Industry

3030. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether as per the Jute Packaging Material Use in Packing Commodities Act it is mandatory for the Fertilizer Industry to pack entire urea production in jute bags;

(b) whether it also stipulates packaging of 65% of the production by cement industry;

(c) whether Government are aware that this Act is being violated and packaging is being done in synthetic bags; and

(d) if so, the details of action taken so far by Government against violators during last three years?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Cement industry and the Urea producing units have violated the provisions of the Act. Under Section 6, 7 and 8 of the Act, the Office of the Jute Commissioner has from time to time, carried out inspections of books and records in 10 cement and 3 Fertilizer units, called for information with particular reference to details of utilisation of jute bags by units and issued 11 show cause notices to some of them for continuing violation.

Delay in issuing the licences for amateur Radio Telegraph Station

3031. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMACHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the issuance of Amateur Radio Telegraph Station Licences is being delayed because of the Police Enquiry Report not coming in time;

(b) whether Government are aware of cases where the persons have passed the Grade-I examinations three years ago but have still not received the licences in spit of Police Enquiry being conducted twice; and

(c) the steps proposed to be taken to issue licences at the earliest?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) and (b) The time taken for Police Enquiry Report varies from case to case. After receipt of this clearance, candidates are requested to send latest photographs and fees for issue of licences. Once these are received, licences are isslued to the candidates.

(c) All efforts are made to expedite completion of formalities and issue of licences at the earliest.

दिल्ली में अनुसूचित जनजाति के पुलिस अधिकारी

3032. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के कितने पुलिस अधिकारी हैं और उनमें से पुलिस उपायुक्तों और थाना प्रभारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) ये अधिकारी कहां-कहां कार्यरत हैं और कब से कार्यरत हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पुलिस उपायुक्त, पुलिस सहायक आयुक्त और थाना प्रभारी के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) (क) दिल्ली पुलिस के उपस्थिति रजिस्टर में 2554 अधिकारी/कार्मिक अनुसूचित जनजाति के हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ 5 पुलिस उपायुक्त, 18 सहायक पुलिस आयुक्त और 44 निरीक्षक शामिल हैं। 3 निरीक्षक इस समय थाना प्रभारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) पुलिस उपायुक्तों तथा थाना प्रभारियों से संबंधित अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है (नीचे देखिए)

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

Meeting of Telephone Advisory Committee at Dibrugarh

3033. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the details of meetings of Telephone Advisory Committee, Dibrugarh (TACD), held

विवरण

पुलिस उपायुक्तों और थाना प्रभारियों का ब्यौरा

क्रमसं॰	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	कब से कार्यरत हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
क.	**पुलिस उपायुक्त**		
1.	श्री पी॰ आर॰ मीणा	पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा)	15.7.92
2.	श्री आर॰ एल॰ मीणा	पुलिस उपायुक्त (राष्ट्रपति भवन)	30.3.93
3.	श्री डी॰ पी॰ मीणा	पुलिस उपायुक्त, उच्चतम न्यायालय (सुरक्षा)	21.5.96
4.	श्री एल॰ एस॰ सेलो	पुलिस उपायुक्त (9वीं वटालियन दिल्ली सशस्त्र पुलिस)	2.1.96
5.	श्री डी॰ एस॰ नोरावत	उप-प्राचार्य (पुलिस प्रशिक्षण स्कूल)	31.7.96
ख.	**थाना प्रभारी**		
6.	श्री टीकाराम मीणा	थाना प्रभारी (शकरपुर)	31.5.95
7.	श्री किरोड़ी लाल मीणा	थाना प्रभारी (तिलक नगर)	31.5.95
8.	श्री ज्ञान सिंह मीणा	थाना प्रभारी (मायापुरी)	26.10.94